RAJYA SABHA

Monday, the 28th March, 1988/
8 Chaitra, 1910 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*461. [*The questioner (Shri Basudeb Mohapatra) was absent. For answer, vide col. 36 infra.*]

पेट्रोल और डीजल की दुकानों/एजेंसियों का आबंटन

*462. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 23 नवम्बर, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1541 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरोजगारी स्नातकों को आबंटित पेट्रोल और डीजल की दुकानें/एजेंसियां उनके द्वारा नहीं चलाई जाती हैं बल्कि चोरी-छिपे वे पैसे वाले लोगों के कब्जे में हैं ; और

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है कि एजेंसियां और दुकानें प्राथमिकता के आधार पर बेरोजगार स्नातकों और गरीब किसानों के परिवारों से संबंधित बेरोजगार व्यक्तियों को ही आबंटित की जाएं और वास्तविक रूप में वे उन्हीं के द्वारा चलायी जायं, और ऐसी व्यवस्था के तहत किसी प्रकार की अदला-बदली न हो, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल उद्योग को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि "बेरोजगार और स्नातक" श्रेणी में दी गई कोई डीलरशिप/एजेंसी से साठगांठ के आधार पर अन्य व्यक्तियों द्वारा चलायी जा रही हैं । वर्तमान नीति/डीलरशिप करार में अनधिकृत व्यक्तियों का वितरणशिपों/डीलरशिपों के अन्तरण तथा "बेनामी" एजेंसियों के रूप में चलने वाली एजेंसियों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था है । वर्तमान नीति में "ओपन" श्रेणी में 55 प्रतिशत का आरक्षण है जिनमें बेरोजगार स्नातकों को वरीयता दी जाती है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सभापति महोदय, एक शब्द तो मंत्री जी ने पूरा-पूरा गलत कर दिया है वह है किसान का और मंत्री जी ने कहा है कि ऐसी कोई जानकारी मंत्री जी को नहीं है । क्या मंत्री जी को यह जानकारी नहीं है कि बेगुसराय जिले के बरौनी में जो पेट्रोल पम्प आपने अनइम्प्लायड को दिया आज उसके कब्जे में नहीं रहने के कारण वह केस चल रहा है । इण्डियन एक्सप्रेस और करट में उसके इंटरव्यू छप चुके हैं । यह तो मैंने एक केस का उदाहरण दिया है जो केस चल रहा है और पता नहीं कैसे आपका विभाग काम करता है, कहता है कि जानकारी नहीं है । यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दूसरा पक्ष मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 55 प्रतिशत स्थान स्नातकों को वरीयता देने की बात कही है अभी तक पिछले एक साल, दो साल या तीन साल के आंकड़े आपके पास हों तो आप देने की कृपा करें और यह बताने की कृपा करें कि इस प्रकार के बेरोजगार स्नातकों को कितने स्थान दिये गये हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, प्रश्न के पहले भाग में माननीय सदस्य ने कहा है कि कोई एक केस चल रहा है । केस चल रहा है यही इस बात का प्रमाण है कि यह साबित नहीं हुआ है कि ऐसा बेनामी पेट्रोल पम्प रन कर रहा है । अगर यह सिद्ध हो गया होता तो हम उसको खत्म कर देते ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मंत्री जी ने कहा कि उनको सूचना नहीं है मैंने कहा कि बरौनी में बेगुसराय में एक अनइम्पलायड का केस चल रहा है

जिसके नाम से दिया गया है उसके दखल मे नही हैं वह केस कर रहा है। इण्डियन एक्सप्रेस और करंट कह रहे है उनमें यह समाचार भी छप चुके हैं। मैंने तो एक केस के बारे मे बताया है लेकिन इस तरह के कई केसेज होंगे जिनकी जानकारी आपके विभाग ने आपको नहीं दी।

श्री ब्रह्म दत्त : इसकी तब होती है जब आ तो कोई शिकायत होती है या जब हम चेकिंग करते हैं। बेनामी जानाकारी आम तौर पर मुश्किल है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने एजेंसी देते समय एजेंसी चलाते वक्त भी इस बात का पूरा प्रबंध किया है और हमें इस बात की चिन्ता रहती है, नियमो मे ऐसे प्रावधान है कि ऐसा सम्भव न हो सके फिर भी अगर कहीं झगड़ा पैदा होता है अगर अदालत में केस है तो यह सिद्ध नही हुआ अगर केस सिद्ध हो जाए तो हम लोग उसको समाप्त कर देगे। जहां तक लाइसेस देने का सवाल है आपने पूछा है कि कितने दिये गये हैं तो 1986–87 के आंकड़े मेरे पास है जो मै आपको दे सकता हूं। हमारे पास इस समय लगभग 14 हजार के करीब डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स हैं जिनमे 465 शैड्यूल्ड कास्ट केटेगरी में हैं, 143 शैड्यूल्ड ट्राइब्स केटेगरी मे हैं और 630 अनइम्पलायड ग्रेजुयेट इंजीनियरिंग की केटेगरी में हैं, 367 फिजिकली हेंडीकेप्ड में है। इस तरह से 12158 साधारण केटेगरी में है ओपन केटेगरी में हैं। यह स्थिति इसलिए है कि पहले इस तरह का रिजर्वेशन नहीं था। अब यह स्थिति थोड़ी-थोड़ी बदलती जाएगी। अब हम ने फ्रीडम फाइटर्ज और फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कोटा फिक्स कर दिया है और अब नयी एजेंसीज जो भी दे रहे है इसी के अनुसार दी जा रही हैं इससे स्थिति मे परिवर्तन हो जाएगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं दूसरा सवाल दोहराना चाहता हूं। आपने सब केटेगरीज के लिए फिक्स किया है लेकिन किसान जिसकी आबादी 70–80 प्रतिशत है उस किसान के लड़के को वरीयता देने का कोई प्रावधान नही है। स्नातकों मे भी वे स्नातक ले पाते है जो शहर के बड़े लोगों के स्नातक लड़के है लेकिन ग्रामीण अंचलों के लड़कों के लिए न तो कोई वरीयता है और न ही वे ले पाते हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई विधिविधान डालेंगे ? आप डीजल के पम्प सेट की दुकान दे रहे हैं और डीजल का काम ग्रामीण क्षेत्रों के अंचलों में अधिक हो रहा है और उन इलाकों में भी आप दुकानें दे रहे हैं तो कम से कम डीजल का लाइसेस आप किसानो के लड़कों को देने का कोई न कोई रास्ता निकालगे ?

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, रास्ता निकाला हुआ है। डीजल के पम्पिंग सेट्स और डिस्ट्रीब्यूटरशिप सिर्फ शहरो मे नही हैं। शहरों में ट्रांसपोर्ट के लिए है लेकिन ग्रामीण इलाको में भी यह आऊटलेट्स होते है। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टरों के लिए और ट्यूबवेल्ज के लिए उनकी जरूरत होती है। जब हम लोग एप्लीकेशंस मांगते है तो यह देखते है कि इसके पास जमीन उपलब्ध है या उस इलाके का रहने वाला है या नही है। यह सब बातें हमारा सेलेक्शन बोर्ड देखता है तो उसमें उनको वरीयता मिल जाती है ग्रामीण इलाकों में। शहरों के इलाकों में जरा मुश्किल होता है। अगर किसान को वरीयता दें जैसे कि माननीय सदस्य कह रहे है तो फिर मजदूरों को भी देनी पड़ेगी या दूसरी भी केटेगरीज है जिनको वरीयता देनी पड़ेगी।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सभापति जी, यह तो किसानों के बारे में एक टालने वाली बात है। डीजल पम्पिंग सेट जो देहातों में है उनको भी लेने के लिए शहरों के लोग जाते हैं और वही लेते है। इसलिए जब तक आप वरीयता के नाम से नहीं करेंगे किसान के साथ साथ चाहे आप मजदूर ही कर दीजिये अगर मजदूर नही चला सकेंगे तो कम से कम किसानों के जो पढ़े लिखे लड़के हैं ग्रामीण अंचलों वाले कर दीजिये तो

भी यह एक उपलब्धि हो जाएगी। आपका बजट भी किसान बजट है।

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, डीलरशिप देते समय यह देखा जाता है कि उस में स्थानीय किसानों के अनइम्पलायड लड़कों के लिए उचित व्यवस्था है। मेरा माननीय सदस्य से नम्र निवेदन है कि भारतीय किसान को इस बात की ज्यादा चिन्ता है कि उनको डीजल मिलता रहे डीजल पम्प की उतनी समस्या नहीं है। हमने भयंकर सूखे की समस्या के बावजूद भी भारतीय किसान को डीजल की कमी नहीं होने दी।

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has been kind enough to say that there are provisions for allotting these agencies to people who are unemployed youths and so on. I would like to know from him, Sir, whether he would consider allotting such agencies and outlets whether for petrol or for gases or fuels to clubs like the Ballooning Club or the Flying Club—they are the actual users—so that they are able to handle the materials satisfactorily for other people as well as for themselves. If he does not have such a provision, would he consider allotting the agencies to actual users of our type of Club in which a large number of unemployed youths are getting training?

SHRI BRAHM DUTTA: Sir, such clubs and institutions can apply in the open category and things will be decided on merit. If they are actual users and they are the actual consumers, they should be considered on merit.

श्री नत्था सिंह : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं उन्होंने अभी-अभी बताया है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए भी कोटा है तो राजस्थान में कितनी एजेंसीज शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को और कौन-कौन से स्थानों पर दी हैं? यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि सन् 1985 में बयाना के लिए जो राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में गैस की एजेंसी के लिए डीलरशिप कायम करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है और 1985–86 तक 42 फार्म भी ले लिये गये हैं। लेकिन डीलरशिप आज तक कायम नहीं हो रही है। ये दो प्रश्नों का जवाब मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, सौभाग्य से मेरे राजस्थान की फिगर्स है, 780 हमारे पास कुल वहां रिटेल आउटलेट डीलरशिप हैं, जिनमें से 29 शैड्यूल्ड-कास्ट्स के पास हैं, 22 शेड्यूल्ड-ट्राइब्ज के पास है, 39 अनएंपलायड ग्रेजुएट के पास हैं, 25 फिजिकली हैंडीकेपड के पास है और 656 ओपेन में हैं। जहां तक बयाना की एल० पी० जी० डीलरशिप का सवाल है, इसके बारे में मुझे मालूम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं साधारणतया बता सकता हूं कि पिछले दो वर्षों में आयल सेलेक्शन बोर्ड, जो केंडीडेट्स का चयन करते हैं संगठित नहीं थे। अभी पिछले वर्ष मई में हमने संगठित कर दिए हैं। जो पुराना काम भी निपटा रहे हैं और अगला काम भी कर रहे हैं। लेकिन बयाना के संबंध में मैं मालूम करके माननीय सदस्य को बता दूंगा।

SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT: Mr. Chairman, Sir, I would like to ask the hon. Minister whether it is a fact that oil and gas agencies are sometimes given to influential persons or politicians by underhand means? When that is the case, the deserving persons, maybe unemployed or others, they have complained. On the basis of those complaints may I know whether an inquiry was held? If not held, is the Minister prepared to hold such an inquiry?

SHRI BRAHM DUTT: Sir, I would like to submit the procedure. There are four selection boards in our country. These four boards are for four regions. The Chairman of the selection board is a retired High Court

Judge and members of the boards are retired IAS men. Whenever such complaints are received, because it is an autonomous body, we ask the Chairman of the concerned Oil Selection Board, who is a retired High Court Judge to investigate the matter, because I cannot supersede the Chairman of the autonomous board.

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI: Mr. Chairman, Sir, I have no doubt about the pious wishes of the Government in regard to the quota that they have reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. But even after this allotment takes place some technical hurdles are created which stand in the way of their getting this allotment. May I know from the hon. Minister whether they are willing to set up a machinery to see that the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people are given the due share that is allotted to them?

SHRI BRAHM DUTT: Mr. Chairman, Sir, we have got our policy and our machinery to oversee all these things and we go strictly according to the reservations which have been provided. We have also provided help from the institutions, and financial institutions, for such categories of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and we examine in the beginning itself that there is no such benami man, and in future also we will not allow any such thing. But in certain cases if he wants to take a partner, he also must belong to that very caste or to that very category to which he himself belongs.

श्री सोहनलाल धूसिया : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि डीफेक्ट अगर कोई दूसरा साबित हो जाये कि इसके पीछे पैसे वाला है और डीजरो वह गरीब आदमी का है तो क्या उस हालत में उसका परमिट आप कैंसिल करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त : माधवर, अगर साबित हो जाय तो उसका तो कैंसिल कर देंगे, चाहे उससे नुकसान शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी को ही पहुंचे, कैंसिल करना ही पड़ेगा।

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Mr. Chairman, Sir, the social objective, in which allocations are being made, that very purpose is lost. Is there a review to see that the persons who are supposed to have got the benefit, there is some improvement in their economic status? At the same time, if there is no review, when will you implement such a review programme so that we can be harsh to the persons who are not making use of the benefits properly?

SHRI BRAHM DUTT: Sir, this is a continuous process. We are reviewing the whole thing continuously and it is our effort to ensure that these agencies are run by them and we always go to any extent to help them financially also through the banks and other institutions and agencies. But if somebody does not want to utilise this opportunity, how can we force him? We ourselves are taking all care that it should be utilised by them. The benefit should actually go to the persons for whom they are meant.

Lavish expenditure by the Rural Electrification Corporation

*463. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Rural Electrification Corporation, New Delhi, is making profits every year by borrowing money from other organisations at a lower rate of interest and charging higher rate of interest there on from the States;

(b) whether it is a fact that while the rate of interest is being increased from time to time, no help is given by the Rural Electrification Corporation to the backward States or to backward areas of different States by extending financial aid at reduced